

कांग्रेस नेताओं की लूट व झूठ की कहानी हर कोई जानता है- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने जमवा रामगढ़ में "मन की बात" सुनने के बाद आमजन को संबोधित किया

जयपुर, 29 मार्च 2026। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जमवारामगढ़ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का श्रवण करने के पश्चात आमजन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को अपनी ही सरकार के खिलाफ अजमेर से जयपुर पैदल मार्च निकालना पड़ा था। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, उनकी पार्टी के नेताओं ने तो उन्हें 'नकारा निकम्मा' कहकर अपमानित किया था, लेकिन हमने उनके उन छालों की भी लाज रखी और माफियाओं को जेल भेजा।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को जमवारामगढ़ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और आमजन को संबोधित किया।

सभी को याद है, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को अपनी ही सरकार के खिलाफ अजमेर से जयपुर पैदल मार्च निकालना पड़ा था। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, उनकी पार्टी के नेताओं ने तो उन्हें 'नकारा निकम्मा' कहकर अपमानित किया था, लेकिन हमने उनके उन छालों की भी लाज रखी और माफियाओं को जेल

भेजा और पेपरलोक पर लगाया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता ने इंतजार शास्त्र की बात करने वालों का झूठ का शास्त्र, भ्रष्टाचार का शास्त्र और जेजेएम घोटाला देखा है। उन्होंने कहा कि समय बड़ा बलवान है। कांग्रेस सरकार में जिनको नकारा निकम्मा कहा, आजकल उनकी दिल्ली

में बहुत चल रही है। इस कारण इंतजार शास्त्र वाले तड़प रहे हैं। जैसा किया है, वैसा भरना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और बड़े नेताजी अपने बेटों को आज भी लॉन्च करने में ही लगे हुए हैं। कांग्रेसी नेता आज भी आपस में लड़ रहे हैं। इनकी लूट और झूठ की कहानी हर कोई जानता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर आज कल कोई इंतजार शास्त्र चला रहा है। लेकिन निगाहें कहीं और मिशाना कहीं और चल रहा है। ये उनकी तड़प है कि दिल्ली का उनका आलाकमान बेरुखी दिखा रहा है और असल में तो उन्हें बुलावे का इंतजार है।

राजग की सरकार बनने से केरल में विकास तेज होगा- मोदी

नई दिल्ली, 29 मार्च। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि केरल में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और यह राज्य में बदलाव का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में केरल में राजग की सरकार बनने पर तेज विकास होगा।

■ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केरल के पलक्कड़ में चुनाव सभा में राज्य में बदलाव की बात कही।

ही गठबंधन भाजपा को एक मजबूत विकल्प मानने लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दोनों दल एक-दूसरे के खिलाफ केवल बयान देते हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं करते।

केरल के पलक्कड़ में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने वाम दलों के नेतृत्व वाले एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दोनों गठबंधनों को भ्रष्ट और सांप्रदायिक करार देते हुए कहा कि उनकी राजनीति केवल वोटबैंक तक सीमित है और उन्हें राज्य के विकास की चिंता नहीं है।

राज्य की आर्थिक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल पर पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है, जो पिछले दस वर्षों में तीन गुना हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पैसा सही दिशा में खर्च नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य में राजग की सरकार बनने पर हर रुपये का हिसाब लिया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार की नीतियों का उल्लेख किया और कहा कि सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। साथ ही, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विदेशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

छत्तीसगढ़ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के बीच रुक-रुक कर फायरिंग हुई। मुठभेड़ के बाद इलाके की तलाशी लेने पर एक नक्सली का शव हथियार सहित बरामद किया गया। मृत नक्सली की पहचान 5 लाख रुपये के इनामी पीपीसीएम कैडर के प्लाटून नंबर 31 के सेक्सन कमांडर मूचाकी कैलाश के रूप में हुई है। वह पलनपाड़ गांव, चिंतलनार धाना क्षेत्र का निवासी था।

पुलिस के अनुसार, मूचाकी कैलाश कई बड़ी नक्सली वारदातों में शामिल रहा था, जिनमें नागरिकों की हत्या, सुरक्षाबलों पर हमले और आईईडी विस्फोट की साजिशें शामिल हैं।

वहीं बस्तर रेंज के आईजी सुन्दरराज पट्टिलंगम ने कहा कि माओवादी कैडरों के पास आत्मसमर्पण और पुनर्वास का अवसर अब अंतिम चरण में है। उन्होंने नक्सलियों से अपील की कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटें और शांतिपूर्ण जीवन अपनाएं। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षाबल सतर्क हैं।

अमेरिका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ऑनलाइन अमेरिकी न्यूज पोर्टल वाईनेटन्यूज़ डॉट ने बताया कि यह ईरान के साथ चल रहे युद्ध से जुड़े यूएस सैन्य विस्तार का हिस्सा है। इसमें ऐसी एम्फोबियस सेनाएं शामिल हैं जो समुद्र-आधारित हमले और जमीनी दलों तरह के ऑपरेशन करने में सक्षम हैं। ऐसी युनिट्स का इस्तेमाल आमतौर पर तेजी से तैनाती के लिए किया जाता है, जिसमें रणनीतिक जगहों को सुरक्षित करना, लोगों को निकालना या तटीय लक्ष्यों पर संभावित हमले करना शामिल है।

कांग्रेस ने प. बंगाल में 284 उम्मीदवारों की घोषणा की

कोलकाता, 29 मार्च। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस ने 284 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। यहां कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी यहां अकेले ही चुनाव लड़ रही है। हालांकि, अभी 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। इस बार कांग्रेस अपने सीनियर नेताओं को भी विधानसभा चुनाव में उतार रही है। अधीर रंजन चौधरी को लंबे समय बाद

■ इस बार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है तथा उसने वरिष्ठ नेताओं को भी मैदान में उतारा है।

क्यास पहले ही लगाए जा रहे थे। मौसम नूर को मालतीपुर से टिकट मिला है। इसके अलावा भी कई सीनियर नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट से कांग्रेस ने प्रदीप प्रसाद को टिकट दिया है। वहीं, बीजेपी ने सुवेदु अधिकारी को ममता के खिलाफ खड़ा किया है। ऐसे में यहां पर ममता बनर्जी, सुवेदु अधिकारी और प्रदीप प्रसाद के बीच त्रिकोणीय लड़ाई हो सकती है।

अमेरिका ने विदेशी प्रोफेशनल्स ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिस पर अमेरिका के तकनीकी और सेवा क्षेत्र लंबे समय से निर्भर हैं। इस नीतिगत बदलाव का सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ सकता है। करीब 70 प्रतिशत एच-1बी वीजा भारतीयों को मिलते हैं, जिनमें से बहुत से लोग आईटी सेवाओं, इंजीनियरिंग और कंसल्टिंग क्षेत्रों में काम करते हैं। अनुमान है कि अमेरिका में एच-1बी वीजा पर काम कर रहे 2.8 लाख से अधिक भारतीय पेशेवरों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। अगर कंपनियों को नए वेतन मानकों को पूरा करना अव्यवहारिक लगता है, तो नौकरी छूटने या वापस लौटने की स्थिति बन सकती है।

■ टी.सी.एस., इंफोसिस, विप्रो व एचसीएल काफ़ी भारतीय प्रोफेशनल्स को अमेरिका में पोस्ट रखते थे। अतः इन कंपनियों को इस रीति-नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा।

फिर से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। कंपनियों लागत के दबाव को कम करने के लिए अमेरिका में स्थानीय कर्मचारियों को ज्यादा रखने, ऑटोमेशन बढ़ाने या काम को दूसरे देशों में शिफ्ट करने की दिशा में कदम उठा सकती हैं।

अगर बड़ी संख्या में भारतीय कामगारों को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़े, तो विदेश से आने वाली धनराशि (रेमिटेंस) पर असर पड़ सकता है, जो विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह नीति ऐसे समय में अनिश्चितता को और बढ़ाती है, जब वैश्विक स्तर पर पहले से ही भू-राजनीतिक तनाव और बदलती आर्थिक प्राथमिकताओं के कारण लोगों का आना-जाना प्रभावित हो रहा है। विदेश में करियर बनाने की योजना बना रहे छात्रों और युवा पेशेवरों के लिए संदेश साफ है, अमेरिका जाने के अवसर अब सीमित और ज्यादा चयनात्मक होते जा रहे हैं।

इसके दूरगामी प्रभाव भारतीय आईटी कंपनियों, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक्नॉलॉजीज पर तत्काल हो सकते हैं, जो लंबे समय से एच-1बी कार्यक्रम के जरिए अपने कुशल कर्मचारियों को अमेरिका भेजती रही हैं। अधिक वेतन देने की बाध्यता से लागत बढ़ेगी, जिससे मुनाफे पर असर पड़ सकता है और कंपनियों को अपने बिजनेस मॉडल पर

व्यक्तिगत पेशेवरों के लिए इसके प्रभाव और भी गंभीर हैं। कई एच-1बी कर्मचारी मध्यम स्तर की नौकरियों में हैं, जहां उनका वेतन शायद संशोधित न्यूनतम सीमा के अनुसार नहीं हो सकता। इससे स्थिति ऐसी बन सकती है

कि केवल बहुत उच्च कौशल वाले या विशिष्ट विशेषज्ञता वाले कर्मचारी ही अमेरिका में काम करने के योग्य रह जाएं, तथा बड़ी संख्या में उम्मीदवार बाहर हो जाएं। भारतीय इंजीनियरों और तकनीकी स्नातकों के लिए अमेरिकन ड्रीम हासिल करना और मुश्किल हो सकता है।

इसका एक व्यापक आर्थिक असर भी हो सकता है। अमेरिका का तकनीकी क्षेत्र पहले से ही आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में यह नीति कंपनियों की भर्ती क्षमता को सीमित कर सकती है। जहां इसका उद्देश्य घरेलू नौकरियों की रक्षा करना है, वहीं आलोचकों का कहना है कि इससे नवाचार और प्रतिस्पर्धा पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

भारत के लिए यह स्थिति मिश्रित हो सकती है। एक तरफ, कुशल पेशेवरों का संभावित "रिवर्स माइग्रेशन" (वापसी) देश के टैलेंट पूल को मजबूत कर सकता है, जिससे स्टार्टअप, फिनटेक और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों को फायदा होगा। दूसरी तरफ,

अंततः, प्रस्तावित एच-1बी वेतन वृद्धि इमिग्रेशन में सिर्फ एक छोटा-मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि अमेरिका वैश्विक प्रतिभा के साथ अपने संबंधों को नए तरीके से तय कर रहा है। भारतीय पेशेवरों और कंपनियों के लिए यह संकेत है कि उन्हें खुद को बदलते हालात के अनुसार ढालना होगा, चाहे वह नए कौशल सीखना हो, नए बाजारों की तलाश करना हो या अपनी कारोबारी रणनीतियों को नया रूप देना हो।

बरनाला में मकान गिरने से तीन मजदूरों की मौत

बरनाला, 29 मार्च। पंजाब के बरनाला जिले के गांव फरवाही में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं। यहां जैक की मदद से ऊपर उठाया जा रहा एक मकान अचानक भरभराकर गिर गया, जिससे उसके अंदर सो रहे तीन मजदूर मलबे में दब गए और उनकी मौत के परिणाम हो गईं। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। हादसे के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई। गुरुद्वारा साहिब से अनाउससमेंट करके लोगों को मदद के लिए बुलाया गया। ग्रामीणों ने मलबा हटाकर तीनों मजदूरों के शव बाहर निकाले। गांव के सरपंच जगसीर सिंह के अनुसार, विशाल कुमार के मकान को जैक की मदद से ऊपर उठाने का काम पिछले कई सप्ताह से चल रहा था। इसके लिए मोगा के एक ठेकेदार को जिम्मेदारी दी गई थी। काम में चार मजदूर लगे हुए थे, जो दिनभर काम करने के बाद उसी मकान में सो जाते थे। शनिवार रात भी तीन मजदूर वहीं सो रहे थे, जबकि एक अपने घर चला गया था। डीएसपी सतवीर सिंह ने बताया कि मकान की नींव में सीवरेज का पानी जाने के कारण वह एक तरफ से कमजोर हो गया था।

ईरान के मिसाइल हमले से इज़रायल के कैमिकल हब में आग लगी

कैमिकल रिसाव की आशंका के कारण इज़रायल ने लोगों को घर में बंद रहने की सलाह दी

तेल अवीव, 29 मार्च। ईरान ने इज़रायल के प्रमुख कैमिकल हब पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। इससे वहां भीषण आग लग गई है। दक्षिणी इज़रायल के नियोजित होवाव औद्योगिक क्षेत्र में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद लगी आग से कैमिकल रिसाव की आशंका से सुरक्षा एजेंसियाँ अलर्ट हो गई हैं। नियोजित होवाव पर हुए इस हमले से जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए, जिनमें धुएँ का भारी गुबार उड़ता नजर आ रहा है।

■ नियोजित होवाव औद्योगिक क्षेत्र इज़रायल का प्रमुख कैमिकल हब है। यहाँ खतरनाक रसायनों का उत्पादन व भंडारण होता है। इस इलाके पर हमले को सिर्फ सैन्य ही नहीं, पर्यावरण व नागरिक सुरक्षा के लिए भी बहुत संवेदनशील माना जाता है।

इज़रायली मीडिया आउटलेट, द टाइम्स ऑफ इज़रायल के अनुसार, दमकल और बचाव दल क्षतिग्रस्त स्टोरेज यूनिट्स को सील करने और स्थिति को काबू में लाने में जुटे हैं। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर

पहुंचा दिया गया है। आसपास के लोगों को घरों में रहने और खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी गई है। आईडीएफ ने भी लोगों को वर्तमान हालात को देखते हुए सावधानी बताने और बाहर न निकलने की सलाह दी है।

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब इज़रायल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। नियोजित होवाव औद्योगिक क्षेत्र इज़रायल का एक प्रमुख कैमिकल और औद्योगिक हब है, जहां कई खतरनाक रसायनों का उत्पादन और भंडारण होता है। ऐसे में इस इलाके पर हमला सिर्फ सैन्य ही नहीं बल्कि

पर्यावरण और नागरिक सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील माना जाता है। अब तक इस घटना में किसी बड़े मानवीय नुकसान को पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है।

हाल के दिनों में ईरान, इज़रायल-अमेरिका जंग के हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। हिजबुल्लाह जैसे ईरान-समर्थित संगठनों और इज़रायल के बीच सीमा पर झड़पें बढ़ी हैं, जबकि इज़रायल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और सहयोगी नेटवर्क को निशाना बनाने की रणनीति अपनाई है।

स्टालिन ने महिलाओं को दो हजार रूपए व लैपटाप का वादा किया

चेन्नई, 29 मार्च। तमिलनाडु में चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी के साथ शुरू हो गया है वादों और दावों का सबसे बड़ा मुकाबला। सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसमें महिलाओं को 2,000 हजार रूपए, पेंशन बढ़ाने और लैपटॉप बांटने जैसे लोकलुभावना वादे किए गए हैं।

■ तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया।

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि इल्लयु अरसी योजना के तहत महिलाओं को वारिश मशीन, ग्राइंडर, टीवी, माइक्रोवेव आदि जैसी अपनी पसंद की चीजें खरीदने के लिए 8000 रुपये दिए जाएंगे। कर न देने वाली सभी महिलाओं को यह सहायता मिलेगी। वे इसे अपने आस-पास की दुकान से खरीद सकती हैं।

कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी बड़े सुधार देखने को मिलेंगे।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए आय की सीमा बढ़ाकर सालाना 5 लाख रुपये कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, इसका कवरेज बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला स्तर से लेकर तालुका स्तर तक के सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधाओं को दोगुना किया जाएगा।

अमेरिका के सभी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वे ट्रम्प सरकार की कई नीतियों से नाराज हैं। उनका गुस्सा खास तौर पर ईरान के साथ बढ़ते तनाव, सख्त इमिग्रेशन कार्रवाई और बढ़ती महंगाई को लेकर है। कई जगहों पर लोगों ने ट्रम्प और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के खिलाफ पोस्टर दिखाए और उन्हें पद से हटाने की मांग की।

नेशनल मॉल तक मार्च करते हुए गए, उनके हाथों में "ताज उतारो, मसखरा" लिखे बैनर थे और वे "कोई राजा नहीं" के नारे लगा रहे थे।

हिमाचल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से अंतर-घाटी संपर्क भी प्रभावित हुआ है। पुलिस ने हिमखलन, भूस्खलन और अचानक हाईवे बंद होने की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया है। सुबह से ही राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम ठंडा हो गया है।

उंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण तापमान में अचानक गिरावट आई है और दिन के तापमान में और कमी आने की संभावना है। राजस्थान में 31 मार्च तक बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है।

प्रवेशोत्सव 2026

राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में पहली बार सत्रारम्भ के साथ शिक्षारम्भ

1 अप्रैल, 2026 से

सत्रारम्भ के साथ ही विद्यार्थियों को मिलेंगे लाभ

- निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें
- निःशुल्क यूनियनफॉर्म डीबीटी
- विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच (शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान)

राजकीय विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाएं

- प्रशिक्षित शिक्षक
- खेल मैदान व खेल सामग्री
- सुविधाजनक विद्यालय भवन
- व्यावसायिक शिक्षा
- स्मार्ट कक्षाएं व आईसीटी लैब्स
- डिजिटल लाइब्रेरी व रीडिंग कॉर्नर
- गतिविधि आधारित शिक्षा (ABL)
- छात्रवृत्ति व पुरस्कार योजनाएं

चलो, राजकीय विद्यालय चलें हम